डाक
ा डाक
क्रमांक
३8 सि. से.
"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2006—चैत्र 13, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

अधिसूचना

एफ 2-11/2006/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

प्त नाम तथा प्रारंभ—

) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 है.

) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

रिभाषाएं—

न नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) ;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा ;

(ग) "गरीबी रेखा के नीचे" से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो ;

(घ) "फीस" से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय शुल्क ;

(ङ) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गए हैं.

3. प्रथम अपील—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे निश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रु. 75) का शुल्क नगद या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा. परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

(3) अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा.

(4) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालिस दिवस से अधिक नही हो, यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी.

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी.

4. द्वितीय अपील—

(1) इस नियम के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को उस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया अथवा जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को प्रथम अपील प्रस्तुति को पैंतालिस दिवस हो गये.

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसकी सत्यापित प्रति देना होगा.

(3) राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रुपये 100/- (रुपये सौ) (यदि आदेश की प्रति डाक से चाही गई हो तो रु. 125) की फीस नगद चालान, मनीआर्डर या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा.

(4) राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति लोक प्राधिकारी और/अथवा जन सूचना अधिकारी और/अथवा अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा.

(5) अपील की सुनवाई हेतु सूचना आयुक्त संबंधित पक्षकारों को कम से कम सात दिवस का नोटिस देगा.

(6) राज्य सूचना आयुक्त का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

आयुक्त के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीस दिवस के अंदर भेजी जाएगी.

4 के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे है से प्रभारित नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

2-11/2006/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ. तांक 17 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 17th March 2006

NOTIFICATION

-11/2006/1/6.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

itle and commencement—

These rules may be called the Chhattisgarh .ight to information (Appeal) rules 2006.

It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

tions—

rules unless the context otherwise requires.-

"Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) ;

"Section" means the sections of the Act ;

"Below poverty line" means such citizen of state of Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh :

"Fees" means the fees payable under the provisions of the Act ;

The word and expressions used but not defined in these rules carry shall meaning as have been assigned to them in the Act.

t Appeal—

Any person who does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7 or is aggrieved by a decision of the state public information officer may within thirty days from the receipt of such a decision prefer an appeal with a fee of Rs. 50/- (Fi

post appeal Rs. 75/-) either in cash or in the form of non-judicial stamp to such officer who is seni in rank to the state pubic Information officer in each public authority. Provided that such officer ma admit the appeal after expiry of the period of thirty days on being satisfied that the applicant w prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal. the name and address of the appellant the basis of the subje matter of the information with the name and the post of the competent authority. the order of th competent authority and payment of fee or not providing information in time. shall be clearly specifie

(3) for hearing of the appeal the appellate authority shall give minimum 7 days notice to the concern Public Information Officer.

(4) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal within such extended period not exceeding a total of fourty five days recording the reasons in writi for the period extended.

(5) The copy of order passed in appeal shall be given free of cost.

4. **Second Appeal—**

(1) A second appeal shall be against the order passed under sub-rule (3) within ninety days from the d on which the order was passed or was actually received to the State Information Commissioner within fourty five days from the date of filing of first appeal.

Provided that the State Information Commissioner may admit the appeal after the expiry the period of ninety days on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause fr filing the appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal the name and addess of the appellant the basis of the subject matter the information with the name and the post of the competent authority and certified copy of the or of the competent authority shall be given.

(3) With the memorandum of appeal filed before the State Information Commissioner the fee of Rs. 10 (rupees one hundred) (for appeal by post Rs. 125/-) in cash or in the form of non-judicial stamp sh be deposited.

(4) The State Information Commissioner shall after giving reasonable opportunity of being hear public authority or state public information officer or appellant as the case may be decide the app assigning the reasons there on.

(5) Information Commissioner shall give minimum 7 days notice to concerned parties.

(6) The decision of the State Information Commissioner shall be final and binding.

5. A copy of the decision of the State Information Commissioner shall be given free of cost, to the appellant if appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges co shall be sent within 30 days.

6. The fee chargeable under rule 3 and 4 shall not be charged from the persons who are below poverty line.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
NAND KUMAR, Secreta

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

)artments are considering every PIO as Public Authority:

)ority: As a common term the Public Authority for one department remains only one, Act again the term Public Authority for one department remains only one. The Act rovided an examination of the Public Authority i.e. one who designates PIOs (i.e)ority that marks PIOs for particular purpose). Section 5(1) provides that every Public hall designate officers as PIOs in all administrative units and offices **under it** to)rmation to persons requesting for the Information. Thus, the PIO and the Public 're both different and PIO can not be considered as Public Authority.

. are transferring the requests-inter department i.e. within the PIOs under the same c Authority:

s under Section 5 (1) and 7(1) clearly defined the duties of the PIOs i.e. either to Information or to reject the request. The PIO can not do any third work not related entioned above and in no way the PIO has been given powers to directly transfer the der Section 6(3). Thus as per the Act the PIO has to initiate the transfer of the other department through the Public Authority-who has designated him. It is he Act provides that the transfer under Section 6(3) can take place through the ority only.

e arrangements to transfer the request through the Public Authority have been made the transfer the request from the Top Most of one department to the Top Most of rtment because the Top Most officer is supposed to know, who under him, as an ding the Information. Otherwise the a PIO of one Public Authority, if demanded of another department may transfer the request to the PIO situated in remote area, olding the desired Information and in that event, if it goes on, it would not be furnish the Information within the stipulated time.

)artments have not understood the meaning of the terms "Information held or under control of the Public Authority of Section 2(j):

cessary and in general not at all possible that the Public Authority holds all the in it's office. It is therefore, the Act provides to furnish the Information through the the Public Authority that Information also which is under the control of the Public vhich in routine course, that Public Authority can call any time from it's subordinate. Information alone has not been made the criteria.

Act intends that a PIO of a particular Public Authority has to collect the Information lleague PIO and furnish to the Applicant. In no way the transfer under Section 6(3) ace within the department i.e. within the PIOs of the same Public Authority nor an an be directed to go to another PIO of the same Public Authority. Accordingly, the m the request has been made, if not holding the Information, is supposed to collect ition from the colleague PIO and furnish to the Applicant, for this purpose the PIOs put at par (i.e. not subordinates).

n Information is under the control of the Public Authority, it is presumed that it is also control of the PIOs of that Public Authority. It is therefore, Section 6(1) permits to ny PIO" of the "concerned Public Authority" not to the "concerned PIO" of the Public Authority." Had it been so the Act would not have provided two terms i.e. der the control." And if only the term "held" had been provided, in that event, it would the obligation of the Applicant to apply to the concerned PIO of the concerned ority.

Departments are considering that the penalties of Section 20(1) and 20(2) are not ndatory:

enalties are mandatory if the Hon'ble Commission is of the opinion that the delay